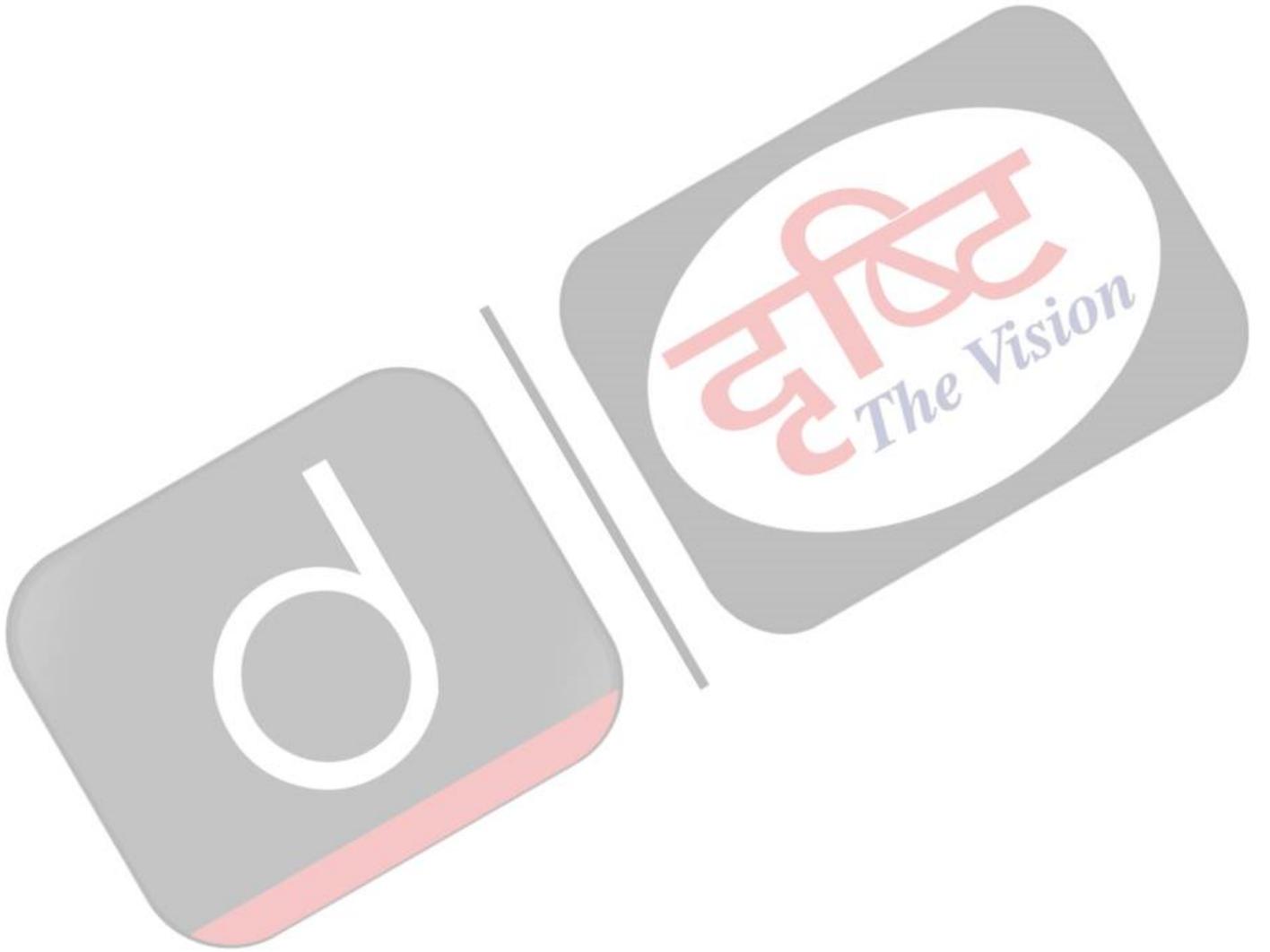


पर्याप्त परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं।





UAE FGCR THEMATIC AREAS

Health

- Risk assessment and monitoring
- Awareness and communications

Infrastructure and settlements

- Risk assessment and management
- Climate smart infrastructure

Cultural heritage

- Climate proofing
- Community engagement

Poverty and livelihoods

- Diversifying livelihoods
- Reskilling in vulnerable sectors

Ecosystems and biodiversity

- Risk assessment and monitoring
- Ecosystem-based approaches
- Community engagement

Food and agriculture

- Climate smart agriculture (techniques and technologies)
- Climate resilient food systems

Water

- Risk assessment and monitoring
- Community engagement
- Regulations

ITERATIVE ADAPTATION POLICY CYCLE

Impact, vulnerability and risk assessment

- Data collection and access
- Risk and vulnerability assessment

Planning

- Capacity assessments
- Cross-sectoral planning and budgeting

Implementation

- Use of adaptation technologies
- Community engagement

Monitoring, evaluation and learning

- Data collection and monitoring
- Institutional learning

ENABLING FACTORS

Data, knowledge and communications

- Communication and knowledge networks
- Data collection and access

Educational and capacity building infrastructure

- Integrating adaptation into education systems
- Training for public officials

Institutional arrangements

- Mainstreaming gender
- Regulations
- Climate literacy in government

Financing

- Proposal preparation
- Climate risk assessment

Engagement

- Gender-responsive outreach and communication
- Networks for dialogue and exchange

Leadership

- Strategic leadership
- Results-based management

Source: Adapted from NAP Global Network (2023) and the UAE FGCR.

विकासशील देशों हेतु जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमिति वित्तीय क्षमता:** समुद्र के किनारे दीवार निर्माण, अनुकूल बुनियादी ढाँचा और जल सुरक्षा जैसी अनुकूलन परियोजनाएँ विकासशील देशों के लिये वित्तीय रूप से बोझिल होती हैं।
- **वकिसति देशों के योगदान में कमी:** जलवायु समझौतों के तहत दायित्वों के बावजूद, वकिसति राष्ट्र वादा किये गए वित्तीय समर्थन (वशेष रूप से वर्ष 2020 के लिये निर्धारित 100 बलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य) को पूरा करने में काफी पीछे हैं।
- उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर निर्भरता: वर्तमान वित्तपोषण का अधिकांश हस्सिसा उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर आधारित है, जससिसे ऋण बोझ बढ़ने के साथ प्राप्तकर्त्ता देशों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।
- **COP29 में वित्तीय प्रतबिद्धता की तात्कालकितता:** वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का लक्ष्य केवल आंशिक रूप से ही इस अंतराल को कम करने में सक्षम है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये गए प्रयास और प्रतबिद्धताएँ क्या हैं?

- **वैश्वक प्रयास:**
 - ग्लासगो जलवायु समझौता और वित्तपोषण लक्ष्य को दोगुना करना: UNFCCC COP26 में वकिसति देशों ने अनुकूलन वित्त को वर्ष 2019 के 19 बलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से वर्ष 2025 तक दोगुना करते हुए 38 बलियन अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2030 तक एक नया जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य स्थापित करने की प्रतबिद्धता व्यक्त की है।
 - **ADB जलवायु अनुकूलन नविश योजना कार्यक्रम (एशियाई विकास बैंक 2023):** यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है जो ADB से संबंधित विकासशील सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन प्राथमकितताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलन नविश योजनाएँ बनाने में सहायता करता है।
 - **UNDP अडैप्टेशन एक्सलेरेटर (UNFCCC 2024): UNDP-अडैप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सलेरेटर (AFCIA)** एक ऐसा कार्यक्रम है जसिके तहत समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रतबिद्धता लचीला बनाने में मदद करने के क्रम में स्थानीय स्तर पर संचालित अनुकूलन प्रथाओं का समर्थन किया जाता है।
- **भारत के प्रयास:**
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2021-2022 में भारत का जलवायु लचीलापन एवं अनुकूलन खर्चसकल घरेलू उत्पाद का 5.6% था।
 - वित्तीय वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण 13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 17% हो गया है।
 - UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (COP26) के 26वें सत्र में भारत ने अपनेराष्ट्रीय स्तर पर अभिनिरिधारित योगदान (NDC) के रूप में पाँच अमृत तत्त्व (पंचामृत) प्रस्तुत किये।

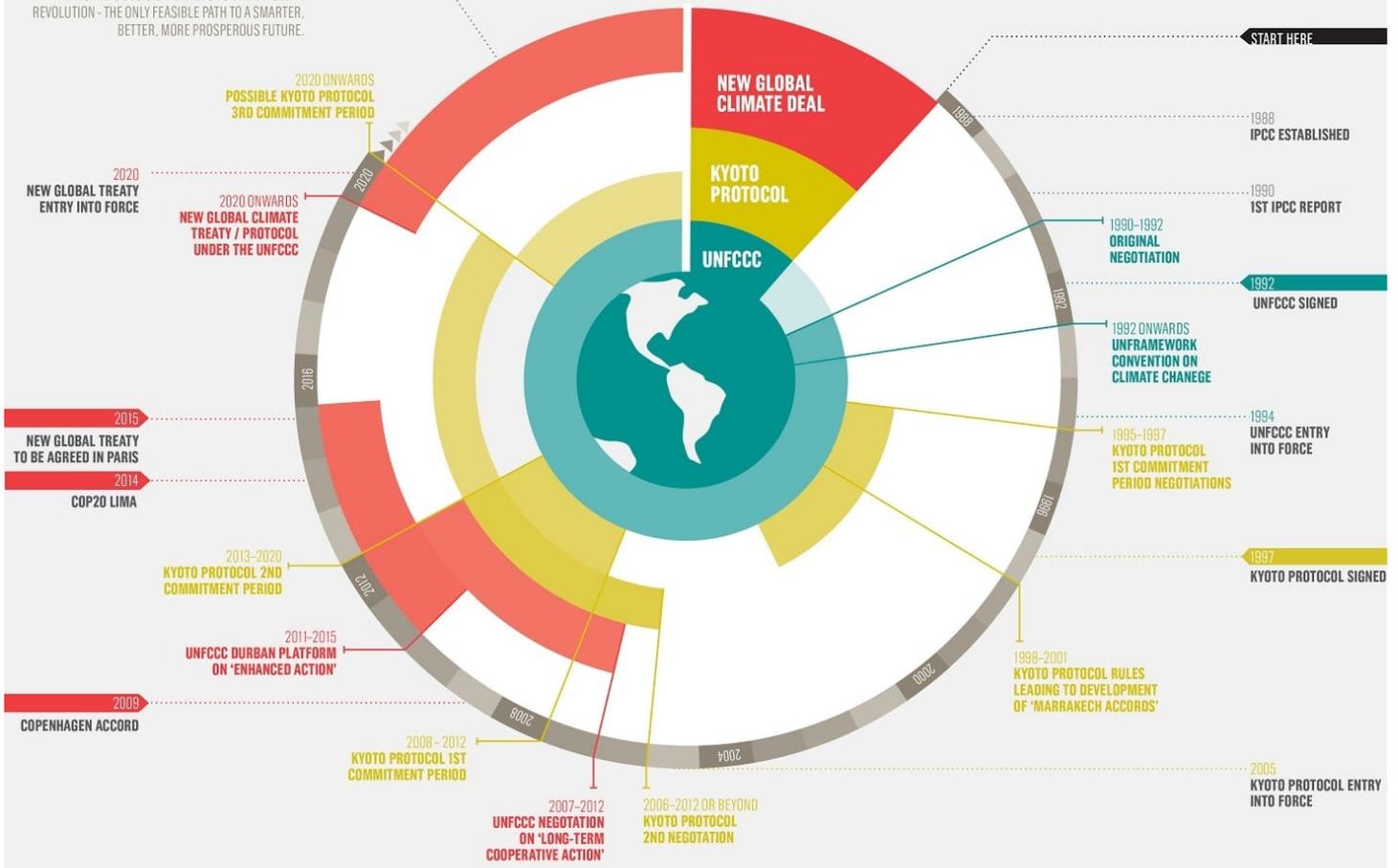
जलवायु वित्तपोषण

- इसका तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है- जो सार्वजनिक, नज्जी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त होता है- जसिका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये शमन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना है।
- UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत वकिसति देशों से अपेक्षा की गई है कविेसमान लेकिन वभिेदित उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत का पालन करते हुए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

आगे की राह

- **मज़बूत वित्तीय व्यवस्था:** इस रिपोर्ट में अनुकूलन प्रयासों को समर्थन देने के लिये मज़बूत वित्तीय प्रतबिद्धता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **वित्तपोषण मॉडल:** इस रिपोर्ट में वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल के रूप में जोखमि वित्त, अनुकूलन बॉण्ड, अनुकूलन हेतु ऋण स्वैप एवं पारस्थितिकी तंत्र सेवा भुगतान का सुझाव दिया गया है।
- **सुधार:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार से गैर-ऋण नधियों तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
- **परिवर्तनकारी प्रभाव:** क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजनाओं के तहत वभिनिन क्षेत्रों में विकास प्राथमकितताओं में अनुकूलन को बढ़ावा देने के साथ परिवर्तनकारी प्रभाव हेतु क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिये।

UNDERSTANDING THE UNFCCC NEGOTIATIONS A TIMELINE OF THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE



THE 'FRAMEWORK' FOR INTERNATIONAL CLIMATE ACTION, UNFCCC

UNFCCC SIGNED - 1992

The original UN climate treaty. Established the basic framework and principles for international climate change action. Developed countries committed to take the lead with developing countries agreeing to take action with financial and technological support as they developed. No legally emission targets agreed for any countries.

NEGOTIATING PROCESS AND COMMITMENT PERIODS OF THE KYOTO PROTOCOL

KYOTO PROTOCOL SIGNED - 1997

Requires industrialized countries to make a collective binding emission cut of 5% below 1990 levels by 2012. Introduced innovative new instruments, including the Clean Development Mechanism. US never ratified. First commitment period (2008-12) covered 50% of 1990 global emissions. Second commitment period coverage down to ~15% as Canada, Japan, Russia and New Zealand join US in opting-out and developing country emissions grow.

NEGOTIATING PROCESSES UNDER THE UNFCCC FOR A NEW GLOBAL CLIMATE DEAL TO COMPLEMENT OR REPLACE THE KYOTO PROTOCOL

COPENHAGEN ACCORD - 2009

Lima must build on the momentum generated by key climate events of 2014 e.g. Ban Ki-moon's Climate Summit in September and China-US announcement in November about limiting emissions. In particular, it must reach agreement on: the elements of a draft negotiating text for new global climate deal; the form and structure of countries' targets and measures for the new deal; and how to enhance ambition in the pre-2020 period. Without these, reaching an ambitious deal at COP21 in Paris next December will be put at risk.

NEW GLOBAL TREATY TO BE AGREED - 2015

Process to agree new treaty covering all countries was established at COP17 Durban in 2011. Governments have to disclose their targets and measures in March, and then conclude negotiations in Paris in December 2015, with treaty in force from 2020. The goal is a global climate agreement covering all countries that will reduce greenhouse gas emissions to a level that will keep the expected rise in Earth's mean surface temperature below 2°C in order to avoid the worst climate change impacts.

नषिकर्ष

अडैप्टेशन गैप रपिर्ट, 2024 में वकिसशील देशों को सहायता देने के क्रम में अनुकूलन वतितपोषण तथा अभनव समाधानों पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान कया गया है। इस रपिर्ट में वैश्वक जलवायु एजेंडे के तहत जलवायु अनुकूलन के महत्त्व को रेखांकति करने के साथ अनुकूलन वतित अंतराल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो UNFCCC COP29 वारता का नरिणायक बदि बना हुआ है।

दृषट मैन्स प्रश्न

प्रश्न: UNEP की अडैप्टेशन गैप रपिर्ट, 2024 में पहचाने गए वैश्वक जलवायु अनुकूलन प्रयासों से संबधति वतितीय एवं रणनीतिक अंतराल पर चर्चा करने के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न: वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2C या कोशिश करें कि 1.5 C से भी अधिक न होने पाए।
3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: "मोमेंटम फॉर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) UNEP सचिवालय
- (c) UNFCCC सचिवालय
- (d) विश्व मौसमविज्ञान संगठन

उत्तर: (c)